ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगी डायग्नोस्टिक सुविधाएं

- एमआरआई और एक्स-रे उपकरण लाने की तैयारी
- एआई आधारित उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 02 जुलाई. प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिये नया कदम उठाया है. इसके तहत प्रदेश चिकित्सा तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक अहम समझौता हुआ है. इसके तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित उपकरण सौंपे जाएंगे.

बता दें इस पहल के तहत मध्य प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें और 308 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरण मिलने जा रहे हैं. इनके आने से राज्य में बीमारियों की शुरुआती जांच और सटीक इलाज की क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही इस नई व्यवस्था से प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर अंचलों में रहने वाले नागरिकों को ये सुविधाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेंगी.

इनका कहना है

पीएम केयर्स के माध्यम से उपलब्ध होने वाले आधुनिक डायग्नोस्टिक से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, मप्र

पोर्टेबल एक्स-रे से घर के पास जांच

308 एआई-इनेबल्ड हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों की मदद से स्वास्थ्य कर्मी दूरदराज के गांवों में जाकर भी मौके पर ही डिजिटल एक्स-रे कर सकेंगे। एआई तकनीक की वजह से बीमारियों की पहचान तुरंत और सटीकता से हो सकेगी।

कैंसर और गंभीर रोगों की पहचान

11 नई मैमोग्राफी मशीनों की तैनाती से प्रदेश में महिलाओं में स्तन कैंसर की शुरुआती जांच को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 13 नई एमआरआई मशीनों से न्यूरो, रीढ़ की हड्डी और अन्य जटिल शारीरिक समस्याओं की जांच सरकारी स्तर पर रियायती या नि:शुल्क दरों पर हो सकेगी।

एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा इलाज

आरोग्य सेतु 2.0 और आयुष्मान ऐप जैसी डिजिटल प्रणालियों के जरिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और 'आभा' खातों के जरिए मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। इससे मरीजों को हर बार पुरानी पर्चियां और भारी-भरकम फाइलें लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जैसी प्रणालियों से अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज और क्लेम की प्रक्रिया बेहद तेज और पारदर्शी हो सकेगी.

नर्मदा क्षेत्र विकास के निर्णय अब हर माह

- हर माह होगी नर्मदा समग्र की बैठक
- नर्मदा परिक्रमा पथ अतिक्रमण मुक्त होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवन रेखा है. यह आबादी नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर ही निर्भर है. नर्मदा हमारी धार्मिक आस्था, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है. इसे हर तरह से निर्मल और अविरल बनाए रख कर नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए. प्रदेश में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जायें.

नर्मदा और इसकी सहायक नदियों सहित पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए समाज को विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाये. उन्होंने कहा कि अब हर महीने नर्मदा समग्र की बैठक में इस नदी क्षेत्र के विकास के निर्णय लिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां नर्मदा के विकास से जुड़ना एक पवित्र काम है. सभी विभाग के अधिकारी पूरे समर्पण से यह काम करें. उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ को पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त कर पथिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाये और परिक्रमा मार्ग पर संकेतक भी लगाए जाए. नर्मदा के तट पर स्थित सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए. उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर जहां मंदिर हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए अन्न क्षेत्र भी स्थापित किए जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ कराने की व्यवस्था भी कराएगी.

18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन होंगे

बैठक में एसीएस शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि नर्मदा नदी के सीमावर्ती प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन किए जाएंगे. मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य, गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे. बैठक में एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि मां नर्मदा के जल को सदैव निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा नमन मिशन तैयार किया गया है.

ई- नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस पुरस्कार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई-नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत साइबर सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में यह सम्मान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया गया. मप्र को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य की दूरदर्शी नीति और तकनीकी श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण है. मप्र शासन ने न केवल नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ और सुगम बनाया है, बल्कि उन्हें एक अभेद्य सुरक्षा आवरण भी प्रदान किया है. नगरीय निकायों से जुड़े लाखों नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत एवं वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पारदर्शी प्रशासन को अक्षुण्ण रखना तथा सुरक्षित आईटी अवसंरचना का निर्माण करना पोर्टल की विशेषता रही है.

शिक्षा व्यवस्था पर जीतू का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई . प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों को गहरे संकट में धकेल दिया है. सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के कारण अब न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.

मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश में स्वीकृत 2.89 लाख शिक्षकीय पदों में से 1 लाख 15 हजार 678 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, जो शिक्षा व्यवस्था से जनता का घटता विश्वास दर्शाती है. पटवारी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती नहीं होने, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के लगभग 5,000 स्कूल भवन जर्जर हैं, 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, 10,000 स्कूल बिजली सुविधा से वंचित हैं और 40,000 स्कूलों में चारदीवारी नहीं है.

तांबा चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश

धार. जिले में निसरपुर और कुक्षी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने निर्माणाधीन क्रूज टर्मिनल से लोहे की प्लेटें तथा किसानों की मोटरों से तांबे के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कबाड़ी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये का चोरी का माल और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार नर्मदा नदी किनारे खारवा नाला, करोंदिया, आमला बावड़ी और पुराना कोठड़ा क्षेत्र में किसानों के खेतों और कुओं से मोटर पंप काटकर तांबे के तार चोरी किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

नाबालिग छात्र को बंधक बनाकर पीटा

प्रेम संबंध का मामला, वीडियो वायरल

मुरैना, 2 जुलाई. जिले के सुमावली थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों के शक में एक नाबालिग छात्र को बंधक बनाकर बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो सुमावली कस्बे के मेला ग्राउंड क्षेत्र का है. वीडियो में दो युवक एक नाबालिग छात्र के पैर रस्सी से बांधकर डंडों से उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया. वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. सुमावली थाना प्रभारी रवी प्रताप सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चौखुटी गांव निवासी नाबालिग छात्र का गांव की ही एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध होने का संदेह था. छात्र मुरैना से कोचिंग कर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान मेला ग्राउंड के पास आरोपियों ने उसे रोककर कथित तौर पर प्रेम संबंधों के शक में बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस ने कहा कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश पुलिस में ई-लीव प्रणाली

विशेष संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई . मध्यप्रदेश पुलिस ने पुलिस कर्मियों की सेवा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और पूर्णत: डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एचआरएमएस) का ई-लीव मॉड्यूल लागू कर दिया है.

एक जुलाई से लागू इस नई व्यवस्था के माध्यम से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन, स्वीकृति और अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति एक ही डिजिटल

प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर लागू की गई यह व्यवस्था कागजी प्रक्रिया को कम करने के साथ-साथ अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी. कर्मचारी अब ई-एचआरएमएस पोर्टल तथा मोबाइल एप के माध्यम से रियल टाइम में अपने अवकाश आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

मानसून ने पूरे एमपी को किया कवर

28 प्रतिशत कम बारिश हुई प्रदेश में

04 दिन भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी

भोपाल, 2 जुलाई . मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और गुरुवार को उसने प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया. राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, रीवा, सीहोर, रतलाम, दमोह और पांढुर्णा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई.

दमोह में लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए, जबकि कई शहरों में दिनभर रुक-रुककर तेज वर्षा होती रही. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेशभर में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

इस वर्ष मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और लगभग नौ दिनों में पूरे प्रदेश में फैल गया. हालांकि इसकी एंट्री सामान्य तिथि की तुलना में करीब नौ दिन देर से हुई. इसके बावजूद जुलाई की शुरुआत के साथ मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है.

मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में औसतन 100.2 मिमी (करीब चार इंच) वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 139.7 मिमी होनी चाहिए थी.

फिलहाल प्रदेश में लगभग 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि विभाग का अनुमान है कि जुलाई में तेज बारिश का सिलसिला इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है. विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है.

विद्यार्थियों ने ली साइबर सुरक्षा की शपथ

- सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरूआत

विशेष संवाददाता

भोपाल,2 जुलाई . साइबर अपराधों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस ने गुरूवार को राज्यव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में साइबर सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित किया.

स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस विशेष पहल में लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालयीन कर्मचारियों ने सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने का संकल्प लिया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा तथा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशन में संचालित इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को साइबर अपराधों के प्रति अधिक सुरक्षित बनाना है. राजधानी भोपाल से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थित विद्यालयों में एक साथ साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया और इंटरनेट के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के महत्व पर विशेष जोर दिया गया.

पेज एक का शेष

मंत्रिमंडल व संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा

सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में किसी वरिष्ठ नेता को उपप्रधानमंत्री नियुक्त करने के राजनीतिक फायदों को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है .बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अमित शाह व राजनाथ सिंह में से किसी को उप प्रधानमंत्री की कुर्सी देकर सरकारी कार्यों को और सुव्यवस्थित करने का फैसला हो सकता है . इतना ही नहीं चर्चा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात , पंजाब व हिमाचल समेत 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यानी मिशन 2027 के लिए भी इस महामंथन में विस्तृत समीक्षा की गई है ताकि चुनावी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए संगठन और सरकार में जिम्मेदारियों का आवंटन किया जा सके . सूत्र बता रहे हैं कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में विपक्षी दलों से पाला बदलकर आए सांसदों को मंत्री पद का इनाम दिया जाए या संगठन के पुराने वफादारों को तरजीह दी जाए, इस पेंच को सुलझाने के लिए इस बैठक में एक विशेष सोशल-इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है .

नरोत्तम को चुनौती दे सकते हैं अनुज भारती

वहीं उनको कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती के पुत्र अनुज भारती चुनौती दे सकते हैं. उपचुनाव में इन दोनों ही दलों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है. हांलाकि नाम अंतिम रूप से तय करने से पहले दोनों ही बड़े दलों के बीच रायशुमारी से लेकर पैनल तैयार करना और फिर उस पर स्वीकृति की मुहर लगाने की औपचारिकता भी होगी. लेकिन ये सब रस्मी ही होने की संभावना है. दोनों ही दलों के उम्मीदवार लगभग तय है.

क्यों है दोनों नेताओं की दावेदारी मजबूत: डॉ. नरोत्तम मिश्रा भाजपा के बेहद कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होती है. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेन्द्र भारती से नजदीकी मुकाबले में 7742 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. उनकी उम्मीदवारी को अभी दतिया से चुनौती देने के लिए भाजपा में कोई और कद्दावर नेता नहीं है, जो कांग्रेस को सीधी चुनौती दे सके, ऐसे में उनको ही टिकट मिलने की संभावना है. वैसे भी वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं. इधर कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव में चुनौती देने वाले राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता शून्य घोषित हो गई है, जिस कारण उपचुनाव हो रहे हैं. राजेन्द्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यदि किसी विधायक, सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वहीं वे 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित हो जाते हैं. भारती फिलहाल अगले 9 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. अभी तक कोर्ट से उन्हें कोई स्टे नहीं मिला है. ऐसे में राजेन्द्र भारती इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे. लिहाजा अब कांग्रेस उनके पुत्र अनुज भारती पर दांव लगा सकती है. कांगेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अनुज भारती ही भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं. उनका ये भी मानना है कि क्षेत्र में राजेन्द्र भारती की जिस तरह से सदस्यता निरस्त की गई, उससे क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति है. इसी सहानुभूति को वोट में तब्दील करने के लिए पिता के बजाय पुत्र पर दांव लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है.

दिलचस्प होगा उपचुनाव: भाजपा संगठन और डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ताकत एक प्लस एक बराबर 11 की ताकत बनाते हैं. लिहाजा ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है. ये उपचुनाव भाजपा और डॉ. मिश्रा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सबब बन गया है. भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापस कब्जा करना चाहेगी. इधर कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सहानुभति की लहर पर सवाल कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा को नजदीकी चुनौती पेश कर सकती है. पिछला चुनाव परिणाम भी बेहद नजदीकी रहा था, ये उपचुनाव भी नजदीकी रह सकता है.

चुनाव आचार संहिता लागू: उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित होते ही दतिया जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

उपलब्धि टॉप टेन में प्रदेश के 10 स्कूल शामिल, कमला नेहरू दूसरे स्थान पर

राष्ट्रीय स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मप्र का डंका

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 02 जुलाई. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मप्र ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. बता दें देश की इस प्रतिष्ठित सूची में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है. जिसमें शहरी वर्ग की श्रेणी में मध्यप्रदेश के 2 शहरों में रतलाम जिले के सांदीपनि विद्यालय जावरा ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है.

वहीं राजधानी के शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक सांदीपनि विद्यालय ने

इसी श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर को गौरवांवित किया है. इसके साथ ही ग्रामीण श्रेणी में देवास जिले की शासकीय माध्यमिक शाला झिकड़ाखेड़ा को देश में दूसरा स्थान मिला है. बता दें प्रदेश के कुल 78,149 स्कूलों ने इस रेटिंग के लिए स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. विभिन्न तकनीकी जांच और कड़े मूल्यांकन के बाद राज्य स्तर से केवल 20 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर के लिए भेजा गया था. इन 20 में से 10 स्कूलों ने अंतिम राष्ट्रीय चयन सूची में अपनी जगह पक्की की.

स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में स्कूलों ने खुद मूल्यांकन करके आवेदन किया था. इन मानकों में मुख्य रूप से सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, बच्चों के लिये अनुकूल शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, बिजली की बचत, बारिश के पानी का संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), परिसर को हरा-भरा बनाना और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली जैसी गतिविधियां शामिल थीं.

चयनित स्कूलों में सरकारी तंत्र का दबदबा

राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए प्रदेश के 10 स्कूलों में से 8 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें 3 सांदीपनि स्कूल भी शामिल हैं. इसके साथ ही सीहोर का महुआखेड़ी टाकीपुर, शाजापुर का भराड़, जबलपुर का कुंडम, शिवपुरी का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आईटीबीपी करेरा और डिंडोरी की आश्रम शाला इंग्लिश मीडियम शाहपुरा शामिल हैं. इसके अलावा इंदौर और कटनी के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने निजी वर्ग में जगह बनाई है.

इनका कहना है

यह सफलता राज्य शासन, लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केंद्र, जिला प्रशासन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और यूनिसेफ मध्य प्रदेश की टीम के साझा प्रयासों का नतीजा है. अब इन 10 सफल स्कूलों के बेहतरीन तौर-तरीकों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा ताकि प्रदेश के अन्य हजारों स्कूल भी इनसे प्रेरणा ले सकें.

हरजिंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14